Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
p-ISSN : 2231–167X, Impact Factor : 2.3982, Volume 07, No. 03, July, 2017, pp. 361-364

सहकारी संस्थाओं का संगठनात्मक ढाँचा एवं प्रबन्ध

डॉ. देवकृष्ण मण्डीवाल*
डॉ. सुमन चौधरी**

अतीतकाल से ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती आयी है तथा वर्तमान समय में भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशिष्ट महत्व है। सही मायने में कृषि एवं पशुपालन इस राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ के रूप में हैं तथा राज्य का सम्पूर्ण अर्थतंत्र इनके इर्द–गिर्द चक्कर लगाता नजर आ रहा है। यहाँ के तीन चौथाई से भी अधिक लोग कृषि एवं कृषि की सहायक क्रियाओं पर प्रत्यक्षतः निर्भर करते हैं। विडम्बना यह रही है कि इनका राज्य के अर्थतंत्र में अतिमहत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 वर्ष पश्चात भी इनकी स्थिति को किसी भी मायने में अच्छा नहीं कह सकते हैं। कृषि आज भी मानसून का जुआ है। पर्याप्त सिचाई सुविधाओं के अभाव में लगभग दो तिहाई से भी अधिक लोग कृषि के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। मानसून समय पर न आने अथवा पर्याप्त बारिश न होने से कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। अकाल एवं अनिश्चितता की स्थिति में कृषि की पैदावार वांछित स्तर पर नहीं होने से कृषक एवं पशुपालकों की स्थिति खराब होना स्वाभाविक है।

समय पर पर्याप्त मात्रा में संस्थागत साख न मिलने की वजह से कृषक एवं पशुपालक वित्त के लिए महाजनों, साहूकारों एवं अन्य निजी स्त्रोतों पर निर्भरत करते हैं। निजी स्त्रोतों से वित्त प्राप्ति काफी मंहगी एवं विपरीत शर्तों पर उपलब्ध होती है। दूसरी ओर कृषकों एवं पशुपालकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान का अपनी उपज से प्राप्त मूल्य से उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। वर्तमान (मई–जून, 2017) में किसान खून पसीने से तैयार अपनी फसल को औने–पौने दामों पर बेचने को विवश है। मसलन अभी किसान को अपना प्याज 200 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विन्टल बेचना पड़ रहा है जबकि व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित जानकारी के अनुसार प्याज की उत्पादन लागत 600 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विन्टल बैठती है। यही स्थिति लहसून के संदर्भ में देखी गयी है। किसान को लहसून 2000 रुपये से 2500 रुपये प्रति क्विन्टल के बीच में बेचना पड़ रहा है, जबकि कृषकों के अनुसार इसकी लागत 3200 रुपये से 3500 रुपये प्रति क्विन्टल पड़ती है। यह स्थिति कमोबेश सरसों, मूंग एवं मोठ की है जहाँ कृषक वर्ग न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने से वंचित है। इसी वजह से परेशान एवं लाचार है। समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त समाचारों के अनुसार कृषक कर्जे में डूबे होने एवं उनके उत्पाद का उचित मूल्य न मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। राजस्थान सरकार ने यद्यपि लहसून की फसल को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदने का निर्णय लिया तथा इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ आदि जगहों पर पाँच केन्द्र खोले गये जिन पर 10,000 क्विन्टल लहसून 3200 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। यह तात्कालिक रूप से तो ठीक हो सकता है लेकिन दीर्धकाल के लिए निश्चित रूप से अपर्याप्त है।

पशुपालकों को दूध का भी लाभदायक मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक ओर उपभोक्ताओं से दूध एवं दूध से निर्मित विभिन्न पदार्थों का अधिक मूल्य लिया जाता है तथा इसके मुकाबले पशुपालकों का दूध का कम मूल्य दिया जाता है। पशुपालक बार–बार दूध का मूल्य बढ़ाने की मांग करते हैं तथा फल–सब्जी एवं दूध की आपूर्ति बंद करने

* प्राचार्य, प्रभा देवी मेमोरियल महाविद्यालय, काबरी डूंगरी, मुण्डोता, आमेर, जयपुर, राजस्थान।
** व्याख्याता, ई.ए.एफ.एम. विभाग, एस.एस. जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।